Advanced International Journal for Research (AIJFR)
E-ISSN: 3048-7641 ● Website: www.aijfr.com ● Email: editor@aijfr.com

"Diversity, Inequality and Marginalization in Indian Society and its Implications for Education"

"भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं उपेक्षाकरण और उसके शिक्षा पर प्रभाव"

(Language-English & Hindi)

Anil Kumar Singh Kushwaha

Assistant Professor, Department- B.Ed., (M.A.- Geography, Philosophy, M.Ed., NET-Geography & Education) Email ID- kushwahaanil046@gmail.com https://orcid.org/0009-0009-0901-1404

Abstract / *सारांश*

Indian society is known for its vast diversity in terms of region, language, religion, caste, and tribe. While this diversity enriches culture and knowledge, it also gives rise to inequalities and marginalization of certain groups. This paper critically examines the dimensions of diversity, inequality, and marginalization in Indian society and analyses their implications for education. The study highlights constitutional provisions, policy measures like RTE 2009 and NEP 2020, and suggests strategies for inclusive and equitable education.

*भारतीय समाज क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति एवं जनजाति की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह विविधता जहाँ एक ओर सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर असमानता और उपेक्षाकरण की स्थिति भी उत्पन्न करती है। इस शोध पत्र में भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं उपेक्षाकरण का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है तथा इनके शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इसमें संवैधानिक प्रावधानों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (*2009*) तथा नई शिक्षा नीति (*2020*) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है और समावेशी शिक्षा के लिए रणनीतियाँ सुझाई गई हैं।*

Keywords / *प्रमुख शब्द*

*"*Diversity, Inequality, Marginalization, Indian Society, Education, Equity, Inclusion, NEP 2020*"*

"विविधता, असमानता, उपेक्षाकरण, भारतीय समाज, शिक्षा, समानता, समावेशन, नई शिक्षा नीति 2020*"*

1. Introduction / प्रस्तावना

India is one of the most diverse countries in the world, home to multiple religions, languages, castes, tribes, and regional identities. This diversity contributes to the richness of Indian culture, yet it also poses challenges in the form of social inequality, discrimination, and marginalization. Education, being both a reflection and an instrument of social change, is deeply impacted by these diversities and inequalities.

भारत विश्व का सबसे विविधतापूर्ण देश है जहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ, जातियाँ, जनजातियाँ और क्षेत्रीय पहचानें विद्यमान हैं। यह विविधता भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है, परंतु इसके कारण समाज में असमानता, भेदभाव और उपेक्षाकरण जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। शिक्षा, जो समाज का दर्पण और परिवर्तन का साधन है, इन विविधताओं और असमानताओं से गहराई से प्रभावित होती है।

2. Objectives of the Study / अध्ययन के उद्देश्य

2.1. To study the nature of diversity in Indian society.

भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप का अध्ययन करना।

2.2. To analyze different forms of inequalities in Indian society.

भारतीय समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार की असमानताओं का विश्लेषण करना।

2.3. To understand the process of marginalization of disadvantaged groups.

वंचित समूहों के उपेक्षाकरण की प्रक्रिया को समझना।

2.4. To examine the implications of diversity, inequality, and marginalization on education.

विविधता, असमानता एवं उपेक्षाकरण के शिक्षा पर प्रभावों का अध्ययन करना।

2.5. To evaluate constitutional and policy measures addressing these challenges.

इन चुनौतियों से निपटने हेतु संवैधानिक एवं नीतिगत उपायों का मूल्यांकन करना।

2.6. To suggest strategies for inclusive and equitable education.

समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. Study the nature of diversity in Indian society. / भारतीय समाज में विविधता के स्वरूप का अध्ययन करना।

3.1 Regional Diversity / क्षेत्रीय विविधता

India is a land of geographical and regional diversities. From the snow-clad Himalayas in the north to the coastal plains in the south, from the deserts of Rajasthan to the fertile Gangetic plains, every region has its own unique identity. These geographical diversities have shaped distinct lifestyles, occupations, food habits, dresses, and traditions. For example, agriculture dominates in the Indo-Gangetic plain, fishing is a major occupation in coastal areas, while pastoralism is common in desert regions. Regional festivals like Bihu (Assam), Pongal (Tamil Nadu), Onam (Kerala), and Lohri (Punjab) highlight this richness.

भारत भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधताओं का देश है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गंगा की उपजाऊ घाटियों तक प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान है। इन भौगोलिक विविधताओं ने जीवन-शैली, व्यवसाय, खान-पान, वस्त्र और परंपराओं को आकार दिया है। उदाहरण के लिए, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कृषि मुख्य व्यवसाय है, तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना प्रमुख है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुपालन सामान्य है। बिहू (असम), पोंगल (तमिलनाडु), ओणम (केरल) और लोहड़ी (पंजाब) जैसे त्यौहार इस क्षेत्रीय विविधता को स्पष्ट करते हैं।

3.2 Linguistic Diversity / भाषाई विविधता

India is home to more than 19,500 languages and dialects as per the Census of India (2011). The Constitution recognizes 22 scheduled languages under the Eighth Schedule. Hindi, spoken by around 44% of the population, serves as a link language, while English plays a significant role in administration, higher education, and technology. Each region has its own mother tongue, which acts as a cultural marker. Linguistic diversity enriches literature, folk traditions, and cultural practices but also poses challenges in terms of medium of instruction, language policy, and communication across regions.

भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 19,500 भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी लगभग 44% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और इसे संपर्क भाषा माना जाता है, जबकि अंग्रेज़ी प्रशासन, उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी मातृभाषा है जो उसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। भाषाई विविधता साहित्य, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध बनाती है, किन्तु शिक्षा के माध्यम, भाषा-नीति और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद में चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है।

3.3 Religious Diversity / धार्मिक विविधता

India is a secular country where multiple religions coexist. Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, and Jainism are the major religions, along with smaller faiths like Zoroastrianism, Judaism, and tribal animistic traditions. Festivals like Diwali, Eid, Christmas, Baisakhi, and Buddha Purnima reflect this pluralism. Religious diversity contributes to cultural richness but also sometimes becomes a source of tension, demanding a spirit of tolerance and secularism in education and society.

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ अनेक धर्म एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख हैं, साथ ही पारसी, यहूदी और आदिवासी आस्थाएँ भी विद्यमान हैं। दीवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्यौहार इस धार्मिक बहुलता का प्रतीक हैं। धार्मिक विविधता सांस्कृतिक समृद्धि का कारण है, परंतु कभी-कभी यह तनाव का भी कारण बन जाती है, जिससे शिक्षा और समाज में सहिष्णुता एवं धर्मनिरपेक्षता की भावना आवश्यक हो जाती है।

3.4 Caste Diversity / जातीय (वर्ण एवं जाति) विविधता

The caste system is one of the most defining features of Indian social structure. Though its rigidity has weakened over time due to modernization, urbanization, and constitutional safeguards, caste continues to play a role in marriage, politics, and social interaction. Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs) form significant sections of society that have historically faced discrimination and exclusion. Caste-based diversity has implications for education, as marginalized castes often face barriers in access, equity, and quality of education.

भारतीय सामाजिक संरचना की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक जाति व्यवस्था है। यद्यपि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और संवैधानिक संरक्षणों के कारण इसकी कठोरता में कमी आई है, फिर भी विवाह, राजनीति और सामाजिक संबंधों में जाति का प्रभाव बना हुआ है। अनुसूचित जातियाँ (SCs), अनुसूचित जनजातियाँ (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और बहिष्करण का सामना करना पड़ा है। जातीय विविधता का शिक्षा पर गहरा प्रभाव है क्योंकि वंचित जातियों को शिक्षा तक पहुँच, समानता और गुणवत्ता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

3.5 Tribal Diversity / जनजातीय विविधता

India is home to more than 705 recognized tribes (Census 2011), constituting about 8.6% of the total population. Tribes such as Bhils, Gonds, Santhals, Nagas, Mizos, and Todas exhibit unique cultural practices, languages, and traditions. Tribal societies are usually close to nature and depend on forests and agriculture. However, due to geographical isolation, poverty, and lack of infrastructure, tribal communities often face exclusion from mainstream development.

Education for tribal children is a major challenge due to language barriers, poverty, and cultural differences.

भारत में 705 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियाँ (जनगणना 2011) पाई जाती हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं। भील, गोंड, संथाल, नागा, मिज़ो और टोडा जैसी जनजातियाँ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाओं और जीवन-शैलियों के लिए जानी जाती हैं। जनजातीय समाज सामान्यतः प्रकृति के निकट रहते हैं और जंगल व कृषि पर निर्भर करते हैं। किन्तु भौगोलिक एकांत, गरीबी और अवसंरचना की कमी के कारण ये मुख्यधारा के विकास से प्रायः वंचित रह जाते हैं। जनजातीय बच्चों की शिक्षा भाषा अवरोध, गरीबी और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण एक बड़ी चुनौती है।

3.6. संक्षेप (Summary)

The diversity of Indian society is multidimensional and contributes to its cultural richness. However, these diversities, when coupled with social hierarchies and economic inequalities, create challenges of integration, equality, and inclusion in education.

भारतीय समाज की विविधता बहुआयामी है और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का आधार भी है। किंतु जब ये विविधताएँ सामाजिक पदानुक्रम और आर्थिक असमानताओं के साथ जुड़ जाती हैं, तो शिक्षा में एकीकरण, समानता और समावेशन की चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

4. To analyze different forms of inequalities in Indian society. / भारतीय समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार की असमानताओं का विश्लेषण करना।

4.1 Economic Inequality / आर्थिक असमानता

Economic inequality in India is a major social concern. Despite being one of the fastest-growing economies, India struggles with unequal distribution of wealth and resources. According to the Oxfam Report (2023), the top 1% of India's population holds more than 40% of the total wealth, while the bottom 50% shares only 3%. Rural-urban divide, unemployment, underemployment, and agrarian distress worsen this inequality. Such disparities restrict access to quality education, healthcare, and social mobility. Children from poor families often drop out of school due to financial constraints, child labor, or lack of educational infrastructure.

भारत में आर्थिक असमानता एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यद्यपि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, फिर भी धन और संसाधनों का वितरण अत्यधिक असमान है। ऑक्सफैम रिपोर्ट (2023) के अनुसार, भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक है, जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 3% है। ग्रामीण-शहरी विभाजन, बेरोजगारी, अधूरा रोजगार और कृषि संकट इस असमानता को और गहरा बनाते हैं।

आर्थिक विषमता के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच संभव नहीं हो पाती। गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर आर्थिक दबाव, बाल श्रम और शैक्षिक अवसंरचना की कमी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं।

4.2 Gender Inequality / लैंगिक असमानता

Gender inequality is another significant challenge in Indian society. Although the Constitution guarantees equality, women continue to face discrimination in education, employment, and decision-making. The female literacy rate (2011 Census) is 65.46%, compared to 82.14% for males. Practices like dowry, female infanticide, and early marriage further reflect deep-rooted patriarchy. In the field of education, girls from rural and marginalized communities face multiple disadvantages due to poverty, cultural restrictions, and safety concerns.

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिए जाने के बावजूद महिलाएँ शिक्षा, रोजगार और निर्णय-निर्माण में भेदभाव का सामना करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। दहेज, भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ गहरे पितृसत्तात्मक ढांचे को दर्शाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण व वंचित वर्ग की लड़कियाँ गरीबी, सांस्कृतिक प्रतिबंध और सुरक्षा कारणों से अधिक कठिनाइयों का सामना करती हैं।

4.3 Social Inequality / सामाजिक असमानता

Social inequality in India is largely shaped by caste, religion, and community. Historically, Dalits, tribals, and backward classes have suffered from untouchability, social exclusion, and restricted access to resources. Despite legal safeguards, caste discrimination persists in villages, affecting access to education, employment, and dignity. Religious minorities also face discrimination, which sometimes translates into lower educational attainment and economic opportunities.

भारत में सामाजिक असमानता का स्वरूप मुख्यतः जाति, धर्म और समुदाय पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार और संसाधनों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ा है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव अब भी मौजूद है, जो शिक्षा, रोजगार और सम्मान की प्राप्ति में बाधा बनता है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ और आर्थिक अवसर सीमित हो जाते हैं।

4.4 Educational Inequality / शैक्षिक असमानता

Educational inequality is both a cause and effect of economic and social disparities. Access to quality education depends on socio-economic status, caste, gender, and location. Elite private schools provide world-class facilities, while government schools in rural areas often suffer from poor infrastructure, shortage of teachers, and low learning outcomes. Dropout rates are high

among SCs, STs, minorities, and girls. Despite initiatives like RTE 2009 and Mid-Day Meal Scheme, gaps remain in terms of equity, inclusion, and quality.

शैक्षिक असमानता आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का कारण भी है और परिणाम भी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग और स्थान पर निर्भर करती है। जहाँ निजी स्कूल आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल अवसंरचना की कमी, शिक्षकों की कमी और कमजोर शैक्षिक परिणामों से जूझते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और लड़कियों में ड्रॉपआउट दर अधिक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और मध्यान्ह भोजन योजना जैसी पहलों के बावजूद समानता और गुणवत्ता में अभी भी अंतर बना हुआ है।

4.5. संक्षेप (Summary)

Inequality in Indian society manifests in multiple forms–economic, gender-based, social, and educational. These inequalities restrict social mobility, perpetuate poverty, and hinder the goal of inclusive education.

भारतीय समाज में असमानता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है–आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक और शैक्षिक। ये असमानताएँ सामाजिक गतिशीलता को सीमित करती हैं, गरीबी को स्थायी बनाती हैं और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को बाधित करती हैं।

5. To understand the process of marginalization of disadvantaged groups. / वंचित समूहों के उपेक्षाकरण की प्रक्रिया को समझना।

5.1 Dalits / अनुसूचित जातियाँ (दलित)

Dalits, historically known as “untouchables,” have been victims of social exclusion for centuries under the caste system. Despite constitutional safeguards such as the abolition of untouchability (Article 17) and reservation policies in education and employment, Dalits continue to face discrimination in rural and urban settings. Marginalization manifests in limited access to land, resources, and quality education. In schools, Dalit children are often subjected to prejudice, bullying, and segregation, which affects their learning outcomes and self-esteem.

दलित, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से “अस्पृश्य” कहा जाता था, सदियों से जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार के शिकार रहे हैं। यद्यपि संविधान ने अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और शिक्षा व रोजगार में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ दी हैं, फिर भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दलित भेदभाव का सामना करते हैं। भूमि, संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच इनके उपेक्षाकरण का प्रमुख कारण है। विद्यालयों में

दलित बच्चों को अक्सर पूर्वाग्रह, अलगाव और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ता है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ और आत्मसम्मान प्रभावित होता है।

5.2 Tribals / अनुसूचित जनजातियाँ

Tribal communities constitute about 8.6% of India's population (Census 2011). They are marginalized due to geographical isolation, poverty, and cultural differences. Many tribal groups live in remote forest areas with minimal access to modern infrastructure. Displacement due to mining, dams, and industrial projects has worsened their condition. In education, language barriers and cultural mismatch between tribal traditions and mainstream curriculum lead to high dropout rates. Schemes like Ashram schools and Eklavya Model Residential Schools aim to address these issues, but challenges remain.

जनजातीय समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं (जनगणना 2011)। ये लोग भौगोलिक एकांत, गरीबी और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण उपेक्षाकृत हैं। अधिकांश आदिवासी समुदाय दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ आधुनिक अवसंरचना का अभाव है। खनन, बांध और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन ने उनकी स्थिति और कठिन बना दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा अवरोध और मुख्यधारा के पाठ्यक्रम से सांस्कृतिक असंगति के कारण इनकी ड्रॉपआउट दर बहुत अधिक है। आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएँ मददगार हैं, परंतु चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

5.3 Minorities / अल्पसंख्यक

Religious minorities such as Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Parsis form about 20% of India's population. Among these, Muslims (14.2%) are the largest minority group. The Sachar Committee Report (2006) highlighted the socio-economic and educational backwardness of Muslims, showing low literacy rates, poor representation in government jobs, and limited access to quality education. Marginalization of minorities often results in social alienation and lack of trust in public institutions.

मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक भारत की लगभग 20% आबादी हैं। इनमें मुसलमान (14.2%) सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) ने मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को उजागर किया था, जिसमें कम साक्षरता दर, सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच प्रमुख है। अल्पसंख्यकों का उपेक्षाकरण प्रायः सामाजिक अलगाव और सार्वजनिक संस्थानों पर विश्वास की कमी को जन्म देता है।

5.4 Women / महिलाएँ

Women, constituting nearly half of India's population, are marginalized due to deep-rooted patriarchy. Issues such as dowry, domestic violence, gender wage gap, and lack of political

representation illustrate their marginalization. In rural areas, many girls drop out of school due to child marriage, household responsibilities, and safety concerns. Although government initiatives like “Beti Bachao, Beti Padhao” and reservations in Panchayati Raj have improved participation, women still face barriers in higher education and leadership positions.

महिलाएँ भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी गहरे पितृसत्तात्मक ढांचे के कारण वे उपेक्षाकृत रहती हैं। दहेज, घरेलू हिंसा, वेतन असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी इनके उपेक्षाकरण को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियों और सुरक्षा कारणों से अनेक लड़कियाँ विद्यालय छोड़ देती हैं। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसी सरकारी योजनाओं और पंचायतों में आरक्षण से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा और नेतृत्व पदों पर महिलाएँ अब भी बाधाओं का सामना करती हैं।

5.5 Persons with Disabilities (PWDs) / दिव्यांगजन

According to Census 2011, around 2.68 crore people in India are persons with disabilities. They are marginalized due to stigma, lack of accessibility, and limited opportunities. Barriers include absence of ramps, Braille materials, trained teachers, and inclusive classrooms. The Rights of Persons with Disabilities Act (2016) emphasizes inclusive education, but implementation gaps persist. Children with disabilities are often excluded from mainstream education, limiting their chances of social and economic mobility.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। सामाजिक कलंक, पहुँच की कमी और सीमित अवसरों के कारण वे उपेक्षाकृत हैं। बाधाओं में रैम्प का अभाव, ब्रेल सामग्री की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और समावेशी कक्षाओं का अभाव शामिल है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम (2016) समावेशी शिक्षा पर बल देता है, लेकिन कार्यान्वयन में अभी भी कई कमियाँ हैं। दिव्यांग बच्चों को प्रायः मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर रखा जाता है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के अवसर सीमित हो जाते हैं।

5.6. संक्षेप (Summary)

Marginalization in Indian society affects Dalits, tribals, minorities, women, and persons with disabilities. Despite constitutional guarantees and policy interventions, these groups continue to face exclusion and discrimination, which directly impacts their educational opportunities and social mobility.

भारतीय समाज में उपेक्षाकरण का शिकार दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और दिव्यांगजन हैं। संवैधानिक गारंटियों और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद ये समूह अब भी बहिष्कार और भेदभाव का सामना करते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक संभावनाएँ और सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है।

6. To examine the implications of diversity, inequality, and marginalization on education. / विविधता, असमानता एवं उपेक्षाकरण के शिक्षा पर प्रभावों का अध्ययन करना।

Marginalization refers to the social process by which certain groups are systematically excluded from meaningful participation in social, economic, political, and educational life. In Indian society, marginalization has historically been rooted in caste, class, gender, tribe, religion, and disability. These groups often face discrimination, deprivation, and lack of opportunities, which hinder their development and full participation in society.

उपेक्षाकरण (Marginalization) उस सामाजिक प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें कुछ समूहों को व्यवस्थित रूप से समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और शिक्षा के मुख्यधारा जीवन से बाहर रखा जाता है। भारतीय समाज में यह उपेक्षाकरण जाति, वर्ग, लिंग, जनजाति, धर्म और दिव्यांगता के आधार पर लंबे समय से मौजूद रहा है। इससे प्रभावित समूह अक्सर भेदभाव, वंचना और अवसरों की कमी का सामना करते हैं।

6.1. Dalits दलित

Dalits, formerly referred to as "untouchables," have been victims of deep-rooted caste-based discrimination. Despite constitutional safeguards such as the abolition of untouchability (Article 17), they continue to experience exclusion, violence, and limited access to education, employment, and social mobility. Reservation policies in education and employment have provided some relief, but challenges remain in their implementation.

दलित लंबे समय से जाति-आधारित भेदभाव के शिकार रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, फिर भी वे सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और शिक्षा व रोजगार में सीमित अवसरों का सामना करते हैं। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण नीति से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

6.2. Tribal Communities जनजातीय समुदाय

India's tribal communities (Adivasis) constitute about 8.6% of the total population (Census 2011). They are marginalized due to geographical isolation, cultural differences, and lack of political representation. Their land rights and access to resources are often violated in the name of development projects, leading to displacement and loss of livelihood. Educationally, tribal children suffer from high dropout rates, language barriers, and limited access to schools.

जनजातीय (आदिवासी) समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा हैं (जनगणना 2011)। भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक भिन्नता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण वे उपेक्षित हैं। विकास परियोजनाओं के नाम पर उनके भूमि-अधिकार छीने जाते हैं, जिससे विस्थापन और जीविकोपार्जन की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। शैक्षिक दृष्टि से, जनजातीय बच्चों में उच्च ड्रॉप-आउट दर, भाषा अवरोध और विद्यालयों की कमी बड़ी चुनौतियाँ हैं।

6.3. Minorities अल्पसंख्यक

Religious minorities, such as Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Parsis, often experience socio-economic disadvantages. The Sachar Committee Report (2006) highlighted the poor educational and economic status of Muslims in India. Marginalization of minorities leads to under-representation in decision-making processes and restricted access to higher education and government services.

मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक कई बार सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े पाए जाते हैं। "सच्चर समिति रिपोर्ट (2006)" ने मुसलमानों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को चिंताजनक बताया। अल्पसंख्यकों का उपेक्षाकरण उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व और उच्च शिक्षा तक पहुँच को सीमित करता है।

6.4. Women महिलाएँ

Women in India face multiple layers of marginalization, intersecting with caste, class, and religion. Gender inequality manifests in restricted access to education, health care, employment, and political participation. Despite constitutional guarantees and legal reforms, issues like child marriage, dowry, domestic violence, and wage discrimination continue to limit women's empowerment.

भारतीय समाज में महिलाएँ बहु-स्तरीय उपेक्षाकरण का सामना करती हैं, जिसमें जाति, वर्ग और धर्म की परतें जुड़ी रहती हैं। लैंगिक असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में स्पष्ट दिखाई देती है। बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा और वेतन भेदभाव जैसी समस्याएँ महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक हैं।

6.5. Persons with Disabilities (PwDs) दिव्यांगजन

Disabled individuals constitute another marginalized group that struggles with physical, social, and institutional barriers. Lack of accessibility in schools, workplaces, and public spaces prevents their inclusion in mainstream society. Although the Rights of Persons with Disabilities Act (2016) emphasizes inclusive education and equal opportunities, practical implementation is limited.

दिव्यांग व्यक्ति भी एक उपेक्षित वर्ग हैं, जो शारीरिक, सामाजिक और संस्थागत अवरोधों से जूझते हैं। विद्यालयों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुँच की कमी उनके समावेशन को रोकती है। "दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016" ने समावेशी शिक्षा और समान अवसरों पर बल दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन सीमित है।

"In summary", marginalization in Indian society is multi-dimensional, affecting millions of people and intersecting with other forms of inequality. It requires comprehensive educational, social, and policy-level interventions to ensure inclusion, equity, and justice.

"संक्षेप में", भारतीय समाज में उपेक्षाकरण बहुआयामी है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसे दूर करने के लिए शिक्षा, समाज और नीति स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

7. To evaluate constitutional and policy measures addressing these challenges. / इन चुनौतियों से निपटने हेतु संवैधानिक एवं नीतिगत उपायों का मूल्यांकन करना।

Marginalization refers to the social process by which certain groups are systematically excluded from meaningful participation in social, economic, political, and cultural life. In Indian society, marginalization is deeply rooted in historical, cultural, and structural inequalities. Various communities, such as Dalits, Adivasis, minorities, women, and persons with disabilities, face continuous disadvantages in terms of access to resources, rights, and opportunities.

'उपेक्षाकरण (Marginalization)' वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ समूहों को समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के मुख्य प्रवाह से अलग कर दिया जाता है। भारतीय समाज में यह समस्या गहराई से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक असमानताओं में निहित है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और दिव्यांगजन विशेष रूप से उपेक्षित वर्गों में आते हैं।

7.1. Dalits (दलित)

Dalits, earlier referred to as "untouchables," have historically been subjected to caste-based discrimination and exclusion. Despite constitutional safeguards and affirmative action policies, they still face barriers in education, employment, and social mobility. Caste prejudices continue to hinder their full participation in mainstream society.

दलित, जिन्हें पहले "अस्पृश्य" कहा जाता था, सदियों से जातिगत भेदभाव और बहिष्कार का शिकार रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण नीति के बावजूद उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिशीलता में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

7.2. Tribal Communities (आदिवासी समुदाय)

Adivasis constitute one of the most marginalized sections of Indian society. They often live in geographically isolated areas, leading to limited access to education, healthcare, and employment opportunities. The displacement caused by industrialization, mining, and large developmental projects has further aggravated their marginalization.

आदिवासी भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक हैं। ये अक्सर भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। औद्योगीकरण और खनन के कारण विस्थापन ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

7.3. Religious Minorities (धार्मिक अल्पसंख्यक)

Muslims, Christians, and other minority communities often face social and economic exclusion. Reports suggest that Muslims, in particular, have lower literacy rates, limited job opportunities, and inadequate representation in government institutions compared to other groups.

मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी सामाजिक एवं आर्थिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। विशेषकर मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर कम, रोजगार के अवसर सीमित और सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व न्यून है।

7.4. Women (महिलाएँ)

Patriarchal structures in Indian society have historically marginalized women by restricting their mobility, denying equal opportunities, and perpetuating gender stereotypes. Although women's participation in education and workforce has increased, gender inequality and gender-based violence still persist.

भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना ने महिलाओं को लंबे समय तक उपेक्षित रखा है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बराबरी का अवसर नहीं मिला। हालाँकि आज उनकी भागीदारी बढ़ी है, फिर भी लैंगिक असमानता और हिंसा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

7.5. Persons with Disabilities (दिव्यांगजन)

Disabled individuals face dual marginalization – one from their physical or mental condition and the other from social stigma. Despite the enactment of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, barriers to inclusive education, employment, and social integration remain widespread.

दिव्यांगजन दोहरी उपेक्षा का सामना करते हैं - एक तो अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण और दूसरा सामाजिक कलंक के कारण। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' लागू होने के बावजूद शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन की राह में बाधाएँ बनी हुई हैं।

"Overall", marginalization in India is not just about social exclusion but also about denial of basic human rights. It has direct implications for education, as marginalized groups often lack access to quality education, thereby perpetuating cycles of poverty and inequality.

"समग्र रूप से", उपेक्षाकरण केवल सामाजिक बहिष्कार नहीं है, बल्कि यह बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने की प्रक्रिया भी है। इसका सीधा असर शिक्षा पर पड़ता है, क्योंकि उपेक्षित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच नहीं मिल पाती, जिससे गरीबी और असमानता का दुष्चक्र बना रहता है।

8. To suggest strategies for inclusive and equitable education. / समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

Education plays a central role in addressing inequalities, but marginalization creates barriers to equal access, participation, and outcomes. The effects of regional, linguistic, religious, caste-based, tribal, and gender-based diversity on education in India can be seen in multiple dimensions.

शिक्षा असमानताओं को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन उपेक्षाकरण (Marginalization) के कारण समाज के कई वर्गों को समान अवसर नहीं मिल पाता। क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जातिगत, जनजातीय और लैंगिक विविधता भारतीय शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित करती है।

8.1.1. Regional Disparities क्षेत्रीय असमानताएँ

Different states and regions in India exhibit uneven educational development. Rural and backward areas often lack quality schools, infrastructure, and trained teachers, resulting in a lower literacy rate compared to urban centers.

भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में शिक्षा का विकास असमान है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, ढाँचा और प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव है, जिससे वहाँ साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है।

8.1.2. Language Barriers भाषा की समस्या

India's multilingual character poses challenges in providing equitable education. Students from non-dominant linguistic backgrounds often struggle in schools where instruction is in another language. The emphasis of the NEP 2020 on mother tongue instruction in early grades is an attempt to bridge this gap.

भारत की बहुभाषिक संरचना शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत करती है। जिन छात्रों की मातृभाषा माध्यम भाषा से भिन्न होती है, उन्हें शिक्षा में कठिनाई होती है। 'नई शिक्षा नीति 2020' ने प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है, ताकि यह समस्या कम हो सके।

8.1.3. Caste and Social Inequality जातिगत असमानता

Caste-based discrimination negatively impacts Dalit and backward-class students. Social stigma, bullying, and lack of resources lead to high dropout rates. Reservation in education has improved access, but socio-cultural barriers still persist.

दलित और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जातिगत भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। इससे उनका विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत (Dropout Rate) अधिक रहता है। शिक्षा में आरक्षण से अवसर बढ़े हैं, लेकिन सामाजिक बाधाएँ अब भी मौजूद हैं।

8.1.4. Tribal Education आदिवासी शिक्षा

Tribal students face geographic isolation, poor access to schools, and cultural disconnection from the mainstream curriculum. Their dropout rates are among the highest in India. Special residential schools like 'Eklavya Model Residential Schools' are initiatives to address this gap.

आदिवासी छात्रों को विद्यालयों तक पहुँच में भौगोलिक कठिनाइयाँ, संसाधनों की कमी और मुख्यधारा के पाठ्यक्रम से असंबद्धता का सामना करना पड़ता है। 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' जैसी योजनाएँ उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं।

8.1.5. Religious Minorities धार्मिक अल्पसंख्यक

Muslim students, in particular, face low representation in higher education. Lack of modernized educational infrastructure in minority-dominated areas contributes to the educational gap. Recommendations from the Sachar Committee highlight the urgent need for policy intervention.

अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम छात्रों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बहुत कम है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है। 'सच्चर समिति' ने इसे दूर करने के लिए कई नीतिगत सुझाव दिए थे।

8.1.6. Gender Inequality लैंगिक असमानता

Girls in rural and marginalized communities often face barriers such as early marriage, lack of sanitation facilities in schools, and cultural restrictions. Schemes like 'Beti Bachao, Beti Padhao' and reservation for women in higher education aim to increase their participation.

ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे - बाल विवाह, विद्यालयों में शौचालय की कमी और सामाजिक प्रतिबंध। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाएँ इस असमानता को कम करने का प्रयास करती हैं।

8.1.7. Persons with Disabilities दिव्यांगजन की शिक्षा

Inclusive education remains a challenge due to inadequate infrastructure, lack of trained teachers, and social stigma. Despite progressive policies, disabled students often remain excluded from mainstream education.

समावेशी शिक्षा अभी भी चुनौतीपूर्ण है। विशेष ढाँचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और सहायक उपकरणों की कमी के कारण दिव्यांग छात्र अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

Thus, marginalization in society translates directly into marginalization in education. Without addressing these issues, the goals of equality, inclusivity, and quality education remain unattainable.

इस प्रकार, समाज में उपेक्षा शिक्षा पर सीधे प्रभाव डालती है। जब तक इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक समानता, समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे।

8.2. Government Policies and Educational Initiatives / सरकारी नीतियाँ और शैक्षिक पहल

The Government of India has introduced various policies and programs to address educational disparities caused by regional, linguistic, caste, tribal, religious, gender, and disability-based marginalization. These initiatives aim to ensure inclusivity, equality, and quality education for all.

भारत सरकार ने विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय, भाषाई, जातिगत, जनजातीय, धार्मिक, लैंगिक तथा दिव्यांगजन आधारित शैक्षिक असमानताओं को दूर करना है। इन पहलों का लक्ष्य शिक्षा में 'समावेशिता, समानता और गुणवत्ता' सुनिश्चित करना है।

8.2. 1. Constitutional Provisions संवैधानिक प्रावधान

i. "Article 21A": Ensures free and compulsory education for children aged 6-14 years.

'अनुच्छेद 21A': 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

ii. "Article 30": Provides minorities the right to establish and administer educational institutions.

'अनुच्छेद 30': अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार।

iii. "Reservation Policies": Ensure access for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs). 'आरक्षण नीति': अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए शिक्षा में अवसर सुनिश्चित करती है।

8.2.2. Right to Education Act (2009) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

i. Makes education a fundamental right. / शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

ii. Mandates 25% reservation in private schools for economically weaker sections (EWS).

निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 25% सीट आरक्षित।

8.2.3. National Education Policy 2020 नई शिक्षा नीति 2020

i. Promotes "mother-tongue-based learning" at the foundational level. 'मातृभाषा आधारित शिक्षा' पर बल।

ii. Focus on "equity and inclusion" for SCs, STs, OBCs, minorities, and girls.

SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और बालिकाओं के लिए 'न्याय और समावेशिता' पर ध्यान।

iii. Encourages "multidisciplinary and flexible curriculum". 'लचीला एवं बहुविषयक पाठ्यक्रम' की व्यवस्था।

iv. Introduces "Gender-Inclusion Fund" and "Special Education Zones".

'लैंगिक समावेशन कोष' तथा 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' की स्थापना।

8.2.4. Tribal and Minority Education Initiatives जनजातीय और अल्पसंख्यक शिक्षा पहल

i. "Eklavya Model Residential Schools (EMRS):" Provide quality education to tribal children.

'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):' आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

ii. "Prime Minister's New 15-Point Programme for Minorities (2006):" Ensures equitable access to education.

'प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम (2006):' अल्पसंख्यकों की शिक्षा में समान अवसर।

iii. "Maulana Azad National Fellowship:" Financial aid for minority students in higher education.

'मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:' उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता।

8.2.5. Schemes for Girls' Education बालिकाओं की शिक्षा हेतु योजनाएँ

i. "Beti Bachao, Beti Padhao:" Promotes girls' education and empowerment.

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:' बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण।

ii. "Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV):" Residential schools for girls from disadvantaged groups.

'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):' वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय।

iii. "National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education."

'बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना'।

8.2.6. Inclusive Education for Disabled Children दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा

i. "Samagra Shiksha Abhiyan:" Promotes inclusive education for children with special needs.

'समग्र शिक्षा अभियान:' विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा।

ii. "Accessible India Campaign (Sugamya Bharat):" Ensures barrier-free infrastructure in schools.

'सुगम्य भारत अभियान:' विद्यालयों में बाधारहित ढाँचा उपलब्ध कराना।

8.2.7. Other Key Initiatives अन्य प्रमुख पहल

i. "Mid-Day Meal Scheme:" Improves attendance and nutritional levels.

'मध्याह्न भोजन योजना:' बच्चों की उपस्थिति और पोषण स्तर में सुधार।

ii. "Scholarships and Fellowship Programs:" Target marginalized groups to encourage higher education.

'छात्रवृत्ति एवं फैलोशिप कार्यक्रम:' वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन।

iii. "Digital India Initiative:"Focus on bridging the digital divide among rural and urban students.

'डिजिटल इंडिया पहल:' ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच डिजिटल खाई को कम करना।

These policies and initiatives demonstrate the government's commitment to achieving "Education for All", while addressing historical and structural inequalities.

इन नीतियों और योजनाओं से यह स्पष्ट है कि सरकार "सभी के लिए शिक्षा" (Education for All) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

9. The impact of diversity, inequality and marginalisation on education शिक्षा पर विविधता, असमानता और हाशिए पर होने का प्रभाव

The diversity, inequality and marginalisation prevalent in Indian society have a profound impact on the education system. Education is not only a medium of knowledge and skills but it is also an important means of social change, equality and empowerment. Its major impacts are presented below:

भारतीय समाज में व्याप्त विविधता, असमानता और उपेक्षाकरण का शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा न केवल ज्ञान और कौशल का माध्यम है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, समानता और सशक्तिकरण का भी महत्वपूर्ण साधन है। नीचे इसके प्रमुख प्रभाव प्रस्तुत हैं:

9.1. शिक्षा तक पहुँच Access to Education

i. Marginalized sections of the society such as Dalits, tribals, minorities and women still do not have equal access to education.

समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएँ अभी भी शिक्षा तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं।

ii. Inequality in school facilities, teacher availability and infrastructure between rural and urban areas affects the quality of education.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालयी सुविधाओं, शिक्षक उपलब्धता और अधोसंरचना में असमानता शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

iii. The Digital Divide has also limited access to education for marginalized communities.

डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) ने भी marginalized समुदायों की शिक्षा तक पहुँच को सीमित कर दिया है।

9.2. समानता और समावेशन (Equity and Inclusion)

i. Education is considered a 'means of equal opportunity', but discrimination based on caste, gender and economic status still exists. शिक्षा को एक 'समान अवसर का साधन' माना जाता है, लेकिन जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर अब भी भेदभाव मौजूद है।

ii. The aim of Inclusive Education is to teach all children in an equal environment, so that they can imbibe social justice and democratic values.

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान वातावरण में पढ़ाना है, ताकि वे सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर सकें।

iii. Disabled students require special teaching methods, materials and resources.

दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षण पद्धति, सामग्री और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

9.3. पाठ्यचर्या सुधार (Curriculum Reforms)

i. Keeping in mind the diversity of Indian society, the curriculum should be made multicultural and inclusive.

भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या को बहुसांस्कृतिक (Multicultural) और समावेशी बनाया जाना चाहिए।

ii. Content should be prepared free from caste, religious and gender biases.

जातिगत, धार्मिक और लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

iii. It is also important to give importance to local languages and cultures in education so that diversity can be respected.

स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को भी शिक्षा में महत्व देना आवश्यक है ताकि विविधता का सम्मान हो सके।

9.4. Educational Policies / शैक्षिक नीतियाँ

i. The Constitution has given the right to education to all citizens (Article 21A, RTE Act 2009).

संविधान ने सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया है (अनुच्छेद 21A, RTE Act 2009)।

ii. The aim of 'New Education Policy 2020 (NEP 2020)' is to ensure quality and inclusive education.

'नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)' का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना है।

iii. Reservation and special schemes in education (such as mid-day meal scheme, scholarships, e-learning) attempt to bring the socially backward classes into the mainstream.

शिक्षा में आरक्षण और विशेष योजनाएँ (जैसे मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति, ई-लर्निंग) सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती हैं।

9.5. Role of Teacher / शिक्षक की भूमिका

i. Teachers are not only imparters of knowledge but also carriers of social change.

शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी होते हैं।

ii. They have the responsibility to develop social equality, tolerance, sensitivity and respect for diversity among the students.

उन्हें छात्रों में सामाजिक समानता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करने की जिम्मेदारी निभानी होती है।

iii. Teacher training institutes should develop inclusive and sensitive teaching methods from this perspective.

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को इस दृष्टिकोण से समावेशी और संवेदनशील शिक्षण पद्धतियाँ विकसित करनी चाहिए।

10. Constitutional and policy measures for the improvement of education / शिक्षा के सुधार हेतु संवैधानिक व नीतिगत उपाय

The Indian Constitution and various educational policies have taken several steps to reduce the diversity, inequality and exclusion prevalent in the society and to make education more equal, inclusive and equitable.

भारतीय संविधान और विभिन्न शैक्षिक नीतियों ने समाज में व्याप्त विविधता, असमानता और उपेक्षाकरण को कम करने तथा शिक्षा को अधिक समान, समावेशी और न्यायसंगत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

10.1. Constitutional Provisions / संवैधानिक प्रावधान

i. 'Article 14': Right of all citizens to equality before the law. 'अनुच्छेद 14': सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार।

ii. 'Articles 15 and 17': Prohibition of discrimination on grounds of caste, religion, sex, place of birth and abolition of untouchability.

'अनुच्छेद 15 और 17': जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन।

iii. 'Article 21A': Right to free and compulsory education for children between 6 and 14 years (Right to Education Act 2009).

'अनुच्छेद 21A': 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right to Education Act 2009)।

iv. 'Articles 29 and 30': Right of minorities to maintain and administer their language, culture and educational institutions.

'अनुच्छेद 29 और 30': अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने और चलाने का अधिकार।

v. 'Article 46': Promote the educational and economic interests of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other weaker sections.

'अनुच्छेद 46': अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

10.2. शिक्षा नीतियाँ (Educational Policies)

i. "National Policy on Education 1968, 1986 and 1992 Amendments": Emphasis on equality, social justice and universal primary education. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 1992 संशोधन": समानता, सामाजिक न्याय और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर बल।

ii. "Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), 2001": To ensure universal primary education.

"सर्व शिक्षा अभियान (SSA), 2001": सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु।

iii. "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), 2009": To increase access to secondary education.

"राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), 2009": माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए।

iv. "Samagra Shiksha Abhiyan (2018)": Emphasis on inclusive and integrated education from pre-school to class 12.

"समग्र शिक्षा अभियान (2018)": प्री-स्कूल से लेकर 12वीं तक समावेशी और एकीकृत शिक्षा पर ज़ोर।

v. "National Education Policy 2020": Emphasis on holistic development, multilingual education, digital education, skill education and inclusion.

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020": समग्र विकास, बहुभाषी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, कौशल शिक्षा और समावेशन पर बल।

10.3. आरक्षण नीतियाँ (Reservation Policies)

i. Reservation in educational institutions and jobs for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and (OBC).

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण।

ii. Special provisions for women and persons with disabilities.

महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी विशेष प्रावधान।

10.4. विशेष कार्यक्रम और योजनाएँ (Special Programs and Schemes)

i. "Mid-Day Meal Scheme": Increasing school attendance and enrolment by providing nutritious food to children.

"मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)": बच्चों को पौष्टिक आहार देकर स्कूल उपस्थिति और नामांकन बढ़ाना।

ii. "Minority Scholarships": For Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Parsi students.

"अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ": मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी छात्रों के लिए।

iii. "Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV)": Residential school for girls from rural and backward areas.

"कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)": ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय।

iv. 'Digital India and E-Pathshala': To increase the reach of digital education.

'डिजिटल इंडिया और ई-पाठशाला': डिजिटल शिक्षा की पहुँच बढ़ाने हेतु।

10.5. समावेशी शिक्षा के उपाय (Measures for Inclusive Education)

i. दिव्यांग बच्चों के लिए 'Integrated Education for Disabled Children (IEDC)' scheme.

ii. Appointment of Special Training Centre & 'Resource Teachers'.

iii. Translation of teaching material into local languages and Braille/Sign Language.

शिक्षण सामग्री का स्थानीय भाषाओं और ब्रेल/सांकेतिक भाषा में अनुवाद।

11. Challenges and Gaps / चुनौतियाँ और शोध-अंतर

Although many constitutional provisions and educational policies have been implemented to address the problems related to diversity, inequality and marginalization in Indian society, many challenges still persist at the ground level.

भारतीय समाज में विविधता, असमानता और उपेक्षाकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान और शैक्षिक नीतियाँ लागू की गई हैं, फिर भी ज़मीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

11.1. Major Challenges / प्रमुख चुनौतियाँ

i. social inequality / सामाजिक असमानता

Caste, religion and gender based discrimination is still seen in both rural and urban areas.

जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव अभी भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखा जाता है।

Children from weaker sections are deprived of education.

कमजोर वर्गों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

ii. Economic inequality / आर्थिक विषमता

Children from poor families do not get access to quality education and resources.

निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों तक पहुँच नहीं मिल पाती।

Digital Divide is further increasing the gap between rural and urban education.

डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) ग्रामीण व शहरी शिक्षा में अंतर को और बढ़ा रहा है।

iii. Linguistic Diversity / भाषायी विविधता

The medium of education in a multilingual society remains a subject of controversy.

बहुभाषी समाज में शिक्षा का माध्यम विवाद का विषय बना हुआ है।

Lack of education in the mother tongue causes many students to drop out of studies.

मातृभाषा में शिक्षा की कमी से कई छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं।

iv. Gender Inequality / लैंगिक असमानता

The education of daughters is still affected by social evils, child marriage and domestic workload.

* बेटियों की शिक्षा अब भी सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह और घरेलू कार्यभार के कारण प्रभावित होती है।

v. Infrastructure Gaps / बुनियादी ढांचे की कमी

Toilets, libraries, washrooms and digital equipment are not available in many laptops. * अनेक विद्यालयों में शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं हैं।

Lack of teachers and quality of training is also a major obstacle.

* शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी एक बड़ी बाधा है।

vi. Challenges for children with special needs / विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए चुनौतियाँ

Resources needed for inclusive education (Braille books, sign language specialists, ramps, ICT tools) are not adequately available to students with disabilities.

* दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक संसाधन (ब्रेल पुस्तकें, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ, रैंप, ICT टूल्स) पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

11.2. Research Gaps / शोध-अंतर

i. The gap between policies and reality / नीतियों और वास्तविकता में अंतर

The Constitution and education policies talk about equality, but they are not fully implemented at the ground level.

* संविधान और शिक्षा नीतियाँ समानता की बात करती हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर उनका पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो पाता हैं।

ii. Limited studies on regional inequality / क्षेत्रीय असमानता पर सीमित अध्ययन

There have been few comparative studies on the state of education in rural and urban, North and South India or tribal areas.

* ग्रामीण व शहरी, उत्तर व दक्षिण भारत या जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति पर तुलनात्मक अध्ययन कम हुए हैं।

iii. Lack of research on inclusive education / समावेशी शिक्षा पर शोध की कमी

There is still not enough research on the educational challenges faced by disabled, minority and transgender children.

* दिव्यांग, अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों पर अभी भी पर्याप्त शोध नहीं हुए हैं।

iv. Quality of education versus mere access / शिक्षा की गुणवत्ता बनाम मात्र सुलभता

Most schemes have focused on enrolment, but there is a lack of research on quality of education and learning outcomes.

* अधिकांश योजनाएँ नामांकन पर केंद्रित रही हैं, पर शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम (learning outcomes) पर शोध की कमी है।

v. Limited studies on inequality in digital education / डिजिटल शिक्षा में असमानता पर सीमित अध्ययन

There is not enough research available on online education and equal access to digital resources.

* ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच पर पर्याप्त अनुसंधान अभी उपलब्ध नहीं है।

12. Implications for Education / शिक्षा के लिए निहितार्थ

The conditions of diversity, inequality and neglect in Indian society have a profound impact on the education system. Education is not only a means of acquiring knowledge, but it is also a means of strengthening social equality, democratic values and national unity. In this context, the following implications related to education emerge –

भारतीय समाज में विविधता, असमानता और उपेक्षाकरण की स्थितियाँ शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती हैं। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का साधन भी है। इस संदर्भ में शिक्षा से जुड़े निम्नलिखित निहितार्थ सामने आते हैं –

12.1. Need for equal opportunity / समान अवसर की आवश्यकता

It is essential to provide equal educational opportunities to all children irrespective of caste, religion, language, gender or economic status.

* सभी बच्चों को जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति से परे समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।

The education system must adopt policies that give priority to the underprivileged and marginalised sections.

* शिक्षा प्रणाली को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए जो वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को प्राथमिकता दें।

12.2. Inclusive Education / समावेशी शिक्षा

Special arrangements will have to be made for disabled, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, minority and transgender children.

* दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ करनी होंगी।

Inclusive classrooms promote a spirit of equality and cooperation by bringing all groups of society on a common platform.

* समावेशी कक्षाएँ समाज के सभी समूहों को एक साझा मंच पर लाकर समानता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती हैं।

12.3. Importance of mother tongue and multilingual education / मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा का महत्व

In the education policy, mother tongue should be made the medium of teaching in primary classes.

* शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण माध्यम बनाया जाना चाहिए।

A multilingual approach can provide students with a balanced knowledge of regional, national and global languages.

* बहुभाषी दृष्टिकोण से छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक भाषाओं का संतुलित ज्ञान मिल सकता है।

12.4. Role of the Teacher / शिक्षक की भूमिका

* Teachers are not just providers of knowledge but agents of social change.

* शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक हैं।

* They must adopt diversity-sensitive, value-based and inclusive teaching methods.

* उन्हें विविधता-संवेदनशील, मूल्य-आधारित और समावेशी शिक्षण पद्धतियाँ अपनानी होंगी।

* Teacher training programmes should focus on diversity, equity and inclusion.

* शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता, समानता और समावेशन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

12.5. Social and emotional learning / सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा

* The education system must inculcate tolerance, brotherhood, democratic values and awareness of human rights in students.

* शिक्षा प्रणाली को छात्रों में सहिष्णुता, भाईचारा, लोकतांत्रिक मूल्य और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करनी होगी।

* Inclusion of life skills and value based education is essential.

* जीवन कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश आवश्यक है।

12.6. Digital Equality / डिजिटल समानता

* The rural-urban gap in online education and ICT-based learning needs to be reduced.

* ऑनलाइन शिक्षा और ICT आधारित शिक्षण में ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करना होगा।

* Governments and institutions need to ensure equal access to digital tools.

* सरकार और संस्थाओं को डिजिटल साधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करनी होगी।

12.7. Policy reforms and implementation / नीतिगत सुधार और कार्यान्वयन

* Policies should not remain only on paper but should be implemented effectively in real life.

* नीतियाँ केवल कागज़ पर न रहकर वास्तविक जीवन में प्रभावी रूप से लागू हों।

* An increase in the education budget, especially for the education of disadvantaged groups, is necessary.

* शिक्षा के बजट में वृद्धि, विशेषकर वंचित समूहों की शिक्षा हेतु, आवश्यक है।

12.8. निष्कर्ष (Conclusion of this Section)

The diversity of Indian society is our strength, but when this diversity turns into inequality and neglect, education is the most affected. Therefore, it is necessary to make education a tool of social justice and equality rather than considering it only a means of literacy. If education is made inclusive, equitable and based on equal opportunities, then it can ensure social harmony and sustainable development in Indian society.

भारतीय समाज की विविधता हमारी शक्ति है, लेकिन जब यही विविधता असमानता और उपेक्षाकरण में बदल जाती है तो शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होती है। अतः शिक्षा को केवल साक्षरता का साधन न मानकर सामाजिक

न्याय और समानता का उपकरण बनाना आवश्यक है। यदि शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत और समान अवसरों पर आधारित बनाया जाए, तो यह भारतीय समाज में सामाजिक समरसता और सतत विकास को सुनिश्चित कर सकती है।

13. Conclusion and Suggestions / निष्कर्ष और सुझाव

13.1. Conclusion / निष्कर्ष

The biggest feature of Indian society is its "diversity". Differences in language, religion, caste, region and gender make the society colorful and multifaceted. But when this diversity turns into "inequality and neglect", it creates obstacles in the path of social unity and educational equality.

भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी "विविधता" है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और लिंग की भिन्नताएँ समाज को रंगीन और बहुआयामी बनाती हैं। किंतु यही विविधता जब "असमानता और उपेक्षाकरण" में बदल जाती है, तो यह सामाजिक एकता और शैक्षिक समानता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है।

Research and analysis shows that -/ शोध और विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि -

* Disadvantaged and marginalised groups have not yet received adequate equal opportunities for education.

* वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों को शिक्षा के समान अवसर अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाए हैं।

* Educational inequalities persist due to caste, class, gender and economic status.

* जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति के कारण शैक्षिक असमानताएँ बनी हुई हैं।

* There have been improvements in education policy, but challenges still exist at the implementation level.

* शिक्षा नीति में सुधार हुए हैं, परंतु कार्यान्वयन स्तर पर अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं।

* There is a need for special attention on inclusive education, multilingual teaching, teacher training and digital equality.

* समावेशी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल समानता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

Hence, it can be concluded that education is not only a means of acquiring knowledge but it is the "most powerful tool" to strengthen social justice, democratic values and national unity.

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन न होकर सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का "सबसे शक्तिशाली उपकरण" है।

13.2. सुझाव / Suggestions

i. 'Ensuring Equal Opportunities'- The government and institutions must ensure that every child, irrespective of social background, receives the right to education without any form of discrimination.

"समान अवसर सुनिश्चित करना" - सरकार और संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिले।

ii. "Inclusive Education" - Special support schemes should be implemented for children belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities, differently-abled groups, and economically weaker sections.

"समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)" - अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष सहायता योजनाएँ लागू करनी चाहिए।

iii. "Mother-Tongue Based Multilingual Education" - Primary education should be provided in the mother tongue, while higher education should adopt a multilingual approach so that students can preserve their cultural identity while also becoming competent in global competition.

"मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा" - प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और उच्च शिक्षा बहुभाषी दृष्टिकोण पर आधारित हो ताकि छात्र अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बन सकें।

iv. "Improvement in Teacher Training" - Teacher education programs must prioritize diversity, equality, and human rights education as essential components of training.

"शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार" - शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता, समानता और मानवाधिकार शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाए।

v. "Bridging the Digital Divide" - It is necessary to provide equal access to digital and technological resources in both rural and urban areas.

"डिजिटल खाई को पाटना" - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी और डिजिटल साधनों की पहुँच को समान बनाना आवश्यक है।

vi. "Social and Value-Based Education" - Education should integrate life skills, human rights, tolerance, democratic values, and constitutional duties.

"सामाजिक और मूल्य शिक्षा" - शिक्षा में जीवन-कौशल, मानवाधिकार, सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक कर्तव्यों को समाहित किया जाए।

vii. "Effective Policy Implementation" - The National Education Policy (2020) and other educational schemes should be implemented at the grassroots level in a transparent and accountable manner.

"नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन" - नई शिक्षा नीति (2020) और अन्य शैक्षिक योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्यान्वयन किया जाए।

14. Final Remark / समापन टिप्पणी

The diversity of Indian society is both its strength and its challenge. When education embraces this diversity in its true sense, it not only disseminates knowledge but also strengthens social harmony, equality, and national unity. Education is the only medium that can reduce inequalities of caste, class, language, religion, gender, and region, while simultaneously making every citizen aware of their rights and responsibilities.

भारतीय समाज की विविधता ही इसकी शक्ति भी है और चुनौती भी। जब शिक्षा इस विविधता को सही रूप में आत्मसात करती है, तो वह न केवल ज्ञान का प्रसार करती है बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्रीय एकता को भी सशक्त करती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकती है तथा प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बना सकती है।

In the present time, the purpose of education cannot remain confined merely to employment; rather, it must establish the values of justice, equality, tolerance, and humanity in society. If education reaches the marginalized and disadvantaged communities and provides them with equal opportunities, it will truly help India emerge as a democratic and egalitarian society.

वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे समाज में न्याय, समानता, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों की स्थापना करनी होगी। यदि शिक्षा वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुँचकर उन्हें समान अवसर प्रदान करती है, तो यह भारत को वास्तव में लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज बनाने में सहायक होगी।

The National Education Policy (NEP) 2020 has taken significant steps in this direction, but its effective implementation requires the collective participation of the government, educational institutions, teachers, parents, and society as a whole. Education will be meaningful only when it reaches every child and transforms them into self-reliant, aware, responsible, and sensitive citizens.

नई शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, किंतु इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, अभिभावक और स्वयं समाज की सामूहिक भागीदारी अनिवार्य है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह हर बच्चे तक पहुँचे और उसे आत्मनिर्भर, जागरूक, उत्तरदायी तथा संवेदनशील नागरिक बनाए।

Thus, it can be concluded that while diversity in Indian society should be regarded as a "strength", inequality must be seen as a "challenge". Education must be designed in such a way that future generations become not only knowledgeable but also value-oriented. Only such education can strengthen Indian democracy and realize the constitutional ideals of "equality, liberty, fraternity, and justice."

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में विविधता को 'शक्ति' और असमानता को 'चुनौती' मानते हुए शिक्षा को ऐसा स्वरूप देना होगा जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल ज्ञानवान बल्कि मूल्यवान भी बनाए। यही शिक्षा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी और "समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय" के संवैधानिक आदर्शों को साकार करेगी।

References-

1. Béteille, A. (1991). 'Society and Politics in India: Essays in a Comparative Perspective.' Oxford University Press.
2. Srinivas, M. N. (2002). 'Social Change in Modern India.' Orient Blackswan.
3. Deshpande, Satish. (2010). 'Contemporary India: A Sociological View.' Penguin Books.
4. Shah, Ghanshyam. (2001). 'Dalit Identity and Politics.' Sage Publications.
5. Chatterjee, Partha. (1997). 'The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories.' Princeton University Press.
6. Singh, Yogendra. (2012). 'Modernization of Indian Tradition.' Rawat Publications.
7. Government of India. (2011). 'Census of India 2011.' Office of the Registrar General & Census Commissioner, New Delhi.
8. Ministry of Education (2020). 'National Education Policy 2020.' Government of India.
9. Dreze, Jean & Sen, Amartya. (2013). 'An Uncertain Glory: India and its Contradictions.' Princeton University Press.
10. Thorat, Sukhadeo & Newman, Katherine. (2010). 'Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India.' Oxford University Press.
11. Nussbaum, Martha. (2000). 'Women and Human Development: The Capabilities Approach.' Cambridge University Press.
12. Deshpande, Ashwini. (2011). 'The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India.' Oxford University Press.
13. Oxfam India. (2023). 'Survival of the Richest: The India Supplement.'
14. Census of India (2011). 'Provisional Population Totals.' Government of India.
15. Ministry of Education (2009). 'Right to Education Act.' Government of India.
16. Thorat, Sukhadeo & Sadana, Nidhi. (2009). 'Caste and Social Exclusion in India.' Oxford University Press.

17. Ministry of Minority Affairs (2006). 'Sachar Committee Report.' Government of India.
18. Xaxa, Virginius. (2008). 'State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India.' Pearson Education.
19. Nussbaum, Martha. (2001). 'Women and Human Development: The Capabilities Approach.' Cambridge University Press.
20. Government of India. (2016). 'Rights of Persons with Disabilities Act.' Ministry of Social Justice & Empowerment.
21. Béteille, André. (2012). 'Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village.' Oxford University Press.
22. Government of India (2006). 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report (Sachar Committee Report).' Cabinet Secretariat, New Delhi.
23. Thorat, Sukhadeo & Newman, Katherine (2010). 'Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India.' Oxford University Press.
24. Xaxa, Virginius (2003). 'Tribes in India: The Struggle for Survival.' Indian Anthropological Society.
25. Government of India (2016). 'The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.' Ministry of Social Justice and Empowerment.
26. Chatterjee, Partha (1997). 'The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories.' Princeton University Press.
27. Thorat, Sukhadeo & Newman, Katherine. (2012). 'Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India.' Oxford University Press.
28. Shah, Ghanshyam. (2001). 'Dalit Identity and Politics.' Sage Publications.
29. Xaxa, Virginius. (2008). 'State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India.' Pearson.
30. Government of India. (2016). 'The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.' Ministry of Social Justice and Empowerment.
31. Ministry of Education (2020). 'National Education Policy 2020.' Government of India.
32. Sachar Committee Report. (2006). 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community in India.' Government of India.
33. Govinda, R. (2002). 'India Education Report: A Profile of Basic Education.' Oxford University Press.
34. Tilak, J.B.G. (2007). 'Education, Society and Development: National and International Perspectives.' APH Publishing.
35. Ministry of Education (2020). 'National Education Policy 2020.' Government of India.
36. Nambissan, Geetha. (2009). 'Excluded and Victimized Children in Schools: Experiences from the Field.' SAGE Publications.
37. Sachar Committee Report. (2006). 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community in India.' Government of India.
38. UNICEF (2019). 'Girls' Education and Gender Equality in India.' UNICEF Report.
39. Government of India. (2009). 'Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE).'

40. Planning Commission of India. (2006). 'Prime Minister's New 15 Point Programme for Minorities.'
41. Ministry of Tribal Affairs. (2019). 'Eklavya Model Residential Schools Guidelines.'
42. Ministry of Women and Child Development. (2015). 'Beti Bachao, Beti Padhao Scheme.'
43. Tilak, J.B.G. (2018). 'Education Policy in India: From Nehru to Modi.' Orient Blackswan.
44. Government of India. (2009). 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.'
45. Ministry of Education. (2020). 'National Education Policy 2020.' Government of India.
46. Kumar, Krishna. (2004). 'What is Worth Teaching?' Orient Blackswan.
47. Nambissan, Geetha B. (2010). 'Exclusion and Discrimination in Schools: Experiences of Dalit Children.' Indian Institute of Dalit Studies, Working Paper Series.
48. Aggarwal, J. C. (2019). 'Theory and Principles of Education.' Vikas Publishing House.
49. Government of India. (1950). 'The Constitution of India.' Ministry of Law and Justice.
50. Ministry of Education. (2020). 'National Education Policy 2020.' Government of India.
51. Tilak, J. B. G. (2007). 'The Kothari Commission and Education in India.' NIEPA.
52. Aggarwal, J. C. (2020). 'Development and Planning of Modern Education.' Vikas Publishing House.
53. Nambissan, Geetha B. (2009). 'Inclusive Education in India: Concerns, Conflicts and Prospects.'
54. Nambissan, G. B. (2010). 'Equity and Quality in Elementary Education: Issues in Policy and Practice.' NUEPA.
55. Jha, Jyotsna & Dhir Jhingran. (2002). 'Elementary Education for the Poorest and Other Deprived Groups.' Manohar Publishers.
56. Govinda, R. (2002). 'India Education Report: A Profile of Basic Education.' Oxford University Press.
57. Kumar, Krishna (2016). 'Politics of Education in Colonial and Post-Colonial India.' Routledge.
58. Tilak, J. B. G. (2014). 'Education for Development in India.' Springer.
59. National Education Policy (NEP), 2020. Government of India.
60. UNESCO (2015). "Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges." Paris: UNESCO.
61. Nambissan, G. B. & Rao, S. (2013). "Sociology of Education in India: Changing Contours and Emerging Concerns." Oxford University Press.
62. Govinda, R. & Bandyopadhyay, M. (2011). "Access to Elementary Education in India: Country Analytical Review." CREATE.
63. Tilak, J. B. G. (2018). "Education and Development in India: Critical Issues in Public Policy and Development." Palgrave Macmillan.